*विकसित भारत के लिए एक सहायक के रूप में वित्तीय क्षेत्र**

एम. राजेश्वर राव

आप सभी को शुभ संध्या। त्रिशूर मैनेजमेंट एसोसिएशन के 31 वें वार्षिक प्रबंधन सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आना वास्तव में खुशी की बात है।

जैसा कि सुकरात ने एक बार कहा था, "एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं।" तीन साल पहले, हमें नहीं पता था कि हम अपने जीवनकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करेंगे - एक महामारी जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी और हमें अज्ञात, अप्रत्याशित और अनदेखी अशांति के बीच से गुजरने के लिए मजबूर करेगी। महामारी की शुरुआत के तीन साल बाद, जब हम अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो यह कोविड-19 के समय की चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के साथ-साथ सीखे गए कुछ सबब का जायजा लेने का एक उपयुक्त समय हो सकता है।

सबसे पहले दिमाग में यह बात आती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देखी गई अनिश्चितता और उथल-पुथल इस वर्तमान पीढ़ी के लिए पहली बार हुई है। अनुभवों, चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मैं महामारी के बाद, वैश्विक और साथ ही, हमारे देश के आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू करता हूं और उसके बाद, संक्षेप में, वित्तीय दुनिया में महामारी द्वारा लाए गए परिवर्तनों और इस परिवर्तन का भारतीय विकास की कहानी से क्या मतलब है, इस पर अपने विचार संक्षेप में रखता हूं।

अर्थव्यवस्था की बहाली और पुनरुद्धार

कोविड से प्रेरित तनाव किसी भी अन्य तनाव जिसे दुनिया ने पहले देखा है, से अलग था। महामारी तेजी से फैली और उसने दुनिया के लगभग हर देश को प्रभावित किया। वित्तीय नियामकों के लिए, यह स्थिति एक पाठ्यक्रम से बाहर के विषय जैसी थी क्योंकि इस बार आर्थिक तनाव अंतर्निहित आर्थिक असंतुलन या वित्तीय बाजार की विफलताओं के कारण नहीं था, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के कारण था। उसने यह एक अनूठा झटका साबित किया, क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था के आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों को प्रभावित किया, जिससे उत्पादन और खपत दोनों प्रभावित हुए। इसका असर यह हुआ कि 2020 में वैश्विक जीडीपी में 3.5 प्रतिशत[1] की गिरावट आई । वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.8 प्रतिशत[2] की गिरावट आई जिससे यह देश के इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकुचन साबित हुआ। मंदी अत्यधिक समकालिक थी - यहां तक कि 1930-32[3] की महामंदी की पराकाष्ठा पर मंदी में घिरे लगभग 85 प्रतिशत देशों के अनुपात से भी ज्यादा, 90 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी देखी गई।

दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने व्यक्तियों, व्यवसायों और वित्तीय बाजारों का समर्थन करने के लिए पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के अभूतपूर्व राजकोषीय और मौद्रिक नीति उपायों के साथ प्रतिक्रिया दी। इसमें बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज, मात्रात्मक सहजता, और ऋण प्रवाह और आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए अन्य उपाय शामिल थे। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, 2021 के मध्य तक, कोविड के जवाब में वैश्विक आर्थिक प्रोत्साहन 16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें अतिरिक्त सरकारी खर्च, राजस्व का नुकसान और तरलता उपाय[4] शामिल हैं, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर है।

कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने और आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए, भारत ने लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये – भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 13 प्रतिशत से अधिक[5] के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की ।

---

* भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा 22 मार्च, 2023 को त्रिशूर मैनेजमेंट एसोसिएशन के 31 वें वार्षिक प्रबंधन सम्मेलन दिया गया मुख्य भाषण - चंदन कुमार, प्रदीप कुमार और प्रमांशु राजपूत द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया जाता है।

1 आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी 2021।

2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकडे https://www.mospi.gov.in/data पर उपलब्ध हैं।

3 अध्याय 1, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21।

4 कोविड-19 महामारी के जवाब में देश के राजकोषीय उपायों का आईएमएफ राजकोषीय निगरानी डेटाबेस, अक्टूबर 2021।

5 https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1693907

डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड को महामारी घोषित किए जाने के कुछ दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपाय सरकार के कार्यकलापों के पूरक बने । रेपो दर को संचयी रूप से 115 बीपीएस (मार्च और मई 2020 के बीच) घटाया गया था और सीआरआर को 27 मार्च, 2020 को एक वर्ष के लिए 1 प्रतिशत अंक कम किया गया था, ताकि तत्काल चलनिधि की बाधाओं को कम किया जा सके। प्रणालीगत चलनिधि को और बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रेपो संचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किए गए थे।

महामारी से राहत प्रदान करने के लिए नियामक उपायों के एक जांच-परखे सेट की भी घोषणा की गई। इन उपायों में छह महीने के लिए सावधि ऋणों पर अधिस्थगन, नकद ऋण/ ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज आस्थगिति, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण का सरलीकरण आदि शामिल थे।

सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए उपायों ने महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से अर्थव्यवस्था को सहारा देने में मदद की और अशांति के दौरान व्यवसायों और व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया। अर्थव्यवस्था को चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई के उपायों ने वित्तीय बाजारों के सामने आनेवाली धन बाधाओं को कम करने में मदद की और उन्हें अपने परिचालन को जारी रखने और अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाया, जिससे आर्थिक गतिविधि का समर्थन हुआ। कमजोर वर्गों और अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की प्रेरणा ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी तत्काल चिंताओं को दूर किया जाए। अगले वर्ष, यानी वित्त वर्ष 2022 में, जनवरी 2022 की ओमीक्रॉन लहर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो गया। नतीजतन, वित्त वर्ष 2022 में उत्पादन वित्त वर्ष 2020[6] के अपने पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली सुधार दर्ज किया।

जहां भारत और दुनिया महामारी से उबरने की उम्मीद कर रहे थे, यूरोप में भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने मौजूदा महामारी से संबंधित तनाव को बढ़ा दिया, विशेष रूप से वस्तुओं के बाजारों को बाधित किया। उथल-पुथल के कारण कीमतों में वृद्धि हुई तथा ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और धातु की कीमतों में अस्थिरता आई, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। पण्य बाजार पर प्रभाव का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मार्च 2022 तक कीमतों में साल-दर-साल वृद्धि प्राकृतिक गैस के लिए 400 प्रतिशत, कोयले के लिए 250 प्रतिशत, कच्चे तेल के लिए 76 प्रतिशत, खाद्य के लिए 30 प्रतिशत और उर्वरकों के लिए लगभग 120 प्रतिशत थी।[7] इन बढ़ी हुई कीमतों ने कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कई दशकों की उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दिया। यूरो क्षेत्र, जर्मनी और ब्रिटेन[8] में मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत तक पहुंच गई। भारत में भी मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो दिसंबर 2022 में घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई। [9]

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में सभी अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित नीतिगत दरों में वृद्धि की। मई 2022 के बाद से, अमेरिका ने नीतिगत दरों में 450 बीपीएस की वृद्धि की है, जबकि यूके और यूरोपीय संघ ने दरों में 300 बीपीएस की वृद्धि की है।

यूरोप में संघर्ष के कारण वित्त वर्ष 2023 में आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं में संशोधन की आवश्यकता थी। गिरावट के बावजूद, भारत के लिए वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास अनुमान लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 में शीर्ष दो तेजी से बढ़ती महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। लंबी वैश्विक चुनौतियों और सख्त मौद्रिक परिस्थितियों के बावजूद, भारत से अभी भी एक स्वस्थ विकास प्रदर्शित करने की उम्मीद है और यह भारत के अंतर्निहित आर्थिक लचीलेपन और अर्थव्यवस्था के विकास चालकों की पुनः प्राप्ति, नवीकरण और उन्हें फिर से सक्रिय करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 6 जनवरी, 2023 को जारी पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) में 2022-23 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि

[6] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़े https://www.mospi.gov.in/data पर उपलब्ध हैं।

[7] आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23।

[8] आईएमएफ, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23।

[9] मौद्रिक नीति समिति के कार्यवृत्त दिसं -22, फ़रवरी-23।

दर 7.0 प्रतिशत बताई गई है, जो निजी खपत और निवेश से प्रेरित है।

दिसंबर 2022 में बैंक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 16.8 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 8.4 प्रतिशत थी। दिसंबर 2022 में कुल जमा में 10.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले यह 9.6 प्रतिशत थी, जिसमें सावधि जमा में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।[10] सरकार ने व्यय मिश्रण को फिर से प्राथमिकता देकर केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय समेकन के रास्ते पर चलना जारी रखा है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है और अगले वित्त वर्ष में यह घटकर 5.9 प्रतिशत होने की संभावना है। जनवरी 2023 में मासिक जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार करने के साथ, कर राजस्व में उछाल बना हुआ है।[11]

यह भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाता है और आज हमें 'अंधेरे क्षितिज पर उज्ज्वल स्थान' के रूप में जाना जाता है। अपनी बात के पहले भाग को समाप्त करने के लिए, मैं कहूंगा कि वास्तव में, पिछले तीन वर्षों में व्याप्त चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने उल्लेखनीय लचीलापन और सामर्थ्य दिखाया है।

नए क्षितिज, साझेदारी और प्राथमिकताएं

आगे बढ़ते हुए, मैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान और विशेष रूप से कोविड अवधि के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा और कैसे यह भारतीय विकास की कहानी का समर्थन करने के लिए तैयार है, इस पर ध्यान केंद्रित करता हूं।

पिछले दशक में देश में बैंकिंग की महत्वपूर्ण पैठ देखी गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत अब तक 48.20 करोड़ लाभार्थी खाते खोले गए हैं और इन खातों में 1.89 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि है।[12] जून 2022 तक, 1.6 लाख से अधिक बैंक शाखाएं हैं, यानी प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 15 शाखाएं हैं। इसके अलावा, 217 लाख एटीएम[13] का नेटवर्क भी है, जिनमें से 47 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा लगभग 32 लाख बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)[14] कार्यरत हैं जो अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करते हैं। 2021 तक, 78 प्रतिशत भारतीय वयस्कों (15 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी) के पास बैंक खाते थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत था।[15] 25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 किलोमीटर के दायरे में हर गांव के लिए 15 बैंकिंग सेवाएं सुलभ बनाई गई हैं, जो 99.94 प्रतिशत गांवों को कवर करती हैं।[16]

इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुए हैं, जिन्हें कोविड के दौरान बढ़ावा मिला। **पहली महत्वपूर्ण गतिविधि वित्त में प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग है**। वित्त में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण साधन रही है जिसने हमें अधिक समावेशी और कुशल वित्तीय पारितंत्र बनाने के लिए सशक्त बनाया है। बैंक पिछले कुछ समय से तकनीकी समाधानों का उपयोग करके अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में नवाचार और वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि, कोविड अवधि के दौरान इसमें तेजी आई जब गतिशीलता एक चुनौती बन गई और प्रौद्योगिकी हमारी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बचाव में आई। परिस्थितियों की मांग ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने और अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। रिज़र्व बैंक ने वीडियो केवाईसी के उपयोग जैसे उचित दिशानिर्देश जारी करके बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी इस यात्रा में सुविधा प्रदान की। हालांकि, यह सब हमारे देश द्वारा इंडिया स्टैक के साथ जनधन - आधार - मोबाइल, तथाकथित जैम ट्रिनिटी, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और अन्य डिजिटल पहलों जैसे एक सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में उठाए गए विशाल कदमों के माध्यम से संभव हुआ, इसने देश को डिजिटल वित्त युग में निर्णायक प्रवेश करने में सक्षम बनाया। दायरा, सार्वजनिक पहुंच और व्यापकता इंडिया स्टैक को अद्वितीय बनाते है, इसने एक अधिक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की है।

मेरी नजर में, इस अवधि के दौरान दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि फिनटेक कंपनियों और बैंकों के बीच नई साझेदारी

[10] एससीबी के जमा और ऋण पर आरबीआई के त्रैमासिक आंकड़े: दिसंबर 2022।

[11] केंद्रीय बजट 2023-24।

[12] मार्च 2023 तक https://www.pmjdy.gov.in ।

[13] आरबीआई के आंकड़े https://www.rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx?atmid=136 पर उपलब्ध हैं।

[14] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2021-22।

[15] विश्व बैंक का ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस।

[16] पूर्वोक्त।

का उद्भव थी। बैंकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों से फिनटेक के साथ तकनीकी साझेदारी का लाभ उठाते हुए देखा जाता है। इस साझेदारी में, फिनटेक अपनी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता का योगदान कर सकते हैं, जबकि बैंक अपनी डोमेन विशेषज्ञता लाते हैं। चैटबॉट्स, मोबाइल ऐप और व्यक्तिगत डिजिटल समाधान जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर, बैंक ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान कर सकते हैं। यह सहयोग बैंकों को अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने और तकनीक-प्रेमी ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति देता है।

हम सभी ने महसूस किया है या अनुभव किया है कि महामारी के बाद की दुनिया में, डिजिटल ऋण तेजी से बढ़ा है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिससे क्रेडिट के पैमाने और गति दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि, एक ही समय में इसने कई व्यावसायिक संचालन समस्याओं को भी जन्म दिया है। यह नियामक के रूप में एक नियामक दुविधा पैदा करता है क्योंकि तब नियामक को एक तरफ अभिनव व्यापार मॉडल द्वारा लाए गए लाभों और दूसरी तरफ उभरते व्यावसायिक आचरण और नियामक चिंताओं को तौलने में संतुलन रखने की आवश्यकता होती है। रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल ऋण पर सिद्धांत आधारित दिशानिर्देश जारी कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया है।

तीसरी महत्वपूर्ण गतिविधि समावेशिता के महत्व पर हमारा ध्यान केन्द्रित करना था। निराशाजनक समय ने हमें याद दिलाया कि उचित समय पर एक छोटी सी मदद भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए दुनिया में बदलाव ला सकती है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने एक समावेशी वित्तीय प्रणाली के निर्माण की दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर दिया है जहां वित्तीय सेवाओं तक पहुंच केवल एक मूल बैंक खाते तक सीमित नहीं है, बल्कि हर किसी के पास क्रेडिट के औपचारिक चैनलों तक पहुंच है और वे हर किसी को, हर जगह, हर समय डिजिटल भुगतान करने के लिए अपने बैंकिंग खाते का उपयोग करने में सक्षम हैं। दर्शकों को इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि आज भारत की भुगतान प्रणाली हमारी रियल टाइम फास्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई के साथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जो मूल्य में प्रति माह लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन और दैनिक मात्रा में लगभग 26 करोड़ लेनदेन करने में सक्षम है।

अगली चीज जो क्रेडिट बाजारों में क्रांति ला सकती है, वह क्रेडिट निर्णय है जो वित्तीय और साथ ही, वैकल्पिक डेटा की उपलब्धता के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। डेटा विश्लेषिकी का लाभ उठाकर, वित्तीय संस्थान ग्राहक व्यवहार, बाजार के रुझान और उभरते जोखिमों में गहरी पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें अधिक सतर्क क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। डेटा-संचालित वित्त केवल जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के बारे में नहीं है; यह नवाचार को चलाने, ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने और सिस्टम के लाभ के लिए टिकाऊ, लचीला वित्तीय मॉडल बनाने के लिए उस जानकारी का उपयोग करने के बारे में है। डेटा के जिम्मेदार उपयोग को सक्षम करने के लिए, आरबीआई ने खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पेश किया है जो ग्राहकों को अपने डेटा को नियंत्रित करने और विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने की अनुमति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह उम्मीद की जाती है कि एए फ्रेमवर्क वैकल्पिक उधार मॉडल जैसे नकदी प्रवाह-आधारित उधार और बाजार ऋण या जिसे हम लोकप्रिय रूप से पीयर-टू-पीयर लेंडिंग के रूप में जानते हैं, के विकास में तेजी लाएगा। इससे स्ट्रीट वेंडर्स सहित छोटे व्यवसायों जिनके पास पारंपरिक संपार्श्विक नहीं हो सकता है, को ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा कि प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उधार परिदृश्य को बदलने के लिए डेटा, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठानेवाले अधिक अभिनव मॉडल उभरेंगे।

महामारी के बाद की चौथी गतिविधि हम नियामकों को वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखने की याद दिलाती है। आईएमएफ द्वारा 'द ग्रेट लॉकडाउन[17]' के रूप में वर्णित कोविड झटके ने सभी तनाव परीक्षण मॉडल और व्यापार निरंतरता योजनाओं को परीक्षण के दायरे में रखा। इसने हमें यह भी याद दिलाया कि वित्तीय प्रणाली बाहरी और आंतरिक किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले झटकों के प्रति संवेदनशील है, और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना हमारे लिए अनिवार्य

[17] विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2020।

है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वित्तीय स्थिरता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह एक आवश्यकता है - क्योंकि जब यह लड़खड़ाता है, तो लहर प्रभाव सबसे शक्तिशाली को भी अपने घुटनों पर ला सकता है। 2008 का वित्तीय संकट इस बात की याद दिलाता है कि वित्तीय स्थिरता सिर्फ एक आदर्श नहीं है, यह एक अच्छी तरह से काम करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक शर्त है।

बैंक वित्तीय प्रणाली की रीढ़ हैं, और वे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण से, बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करना और नुकसान को सहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखना आवश्यक है। वित्तीय स्थिरता का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व मजबूत शासन है। मजबूत शासन किसी भी संगठन की स्थिरता और समृद्धि की आधारशिला है, अखंडता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय हितधारकों के सर्वोत्तम हित में लिए जाते हैं।

इसे स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने हमेशा अभिशासन पर अधिक महत्व दिया है और बैंकों में इसे मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब बैंकों के लिए एक अलग और स्वतंत्र निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसमें कुछ न्यूनतम योग्यता और अनुभव के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का मिश्रण हो। निदेशक मंडल का निरीक्षण संतुलित जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

भविष्य की चुनौतियां और अवसर

हालांकि, हम सभी बैंकिंग सेवा प्रदान करने की अपनी खोज में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। शहरी और ग्रामीण भारत द्वारा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में भारी अंतर एक चुनौती है। यह हमें एक बड़ा अवसर देती है क्योंकि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल बचत और ऋण तक पहुंच प्रदान करना नहीं है, यह व्यक्तियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने और एक संपन्न अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने से संबंधित है।

वित्तीय समावेशन को ऐसे उत्पादों और सेवाओं को विकसित करके फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उनकी आय के स्तर के आधार पर सबसे उपयुक्त हैं। इसमें अभिनव समाधान शामिल होंगे जो लोगों के लिए न केवल बुनियादी बल्कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना भी आसान बनाते हैं। इस दिशा में और आसान, पर्याप्त और अनुकूलित ऋण को सक्षम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विभेदित बैंकिंग लाइसेंस के लिए प्रावधान किए हैं। ये आला बैंक हैं जो व्यापक और विविध स्पेक्ट्रम में बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं।

भारत के ऋण बाजार में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच लगातार अंतर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत, इसके विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में 48 प्रतिशत का योगदान देता है। इसे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अवसर के क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए।

ध्यान केन्द्रित करने योग्य एक और उभरता हुआ क्षेत्र कम-कार्बन अर्थव्यवस्था में अंतरण के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। हम सभी अब उस वैश्विक चुनौती से अवगत हैं जो जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के लिए पैदा कर रहा है और इसका प्रभाव दुनिया भर में गूंज रहा है। यदि हम समय पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो परिणाम अपरिवर्तनीय होंगे। भारत सरकार पहले ही 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन एक बिलियन टन तक कम करने, 2030 तक कार्बन अर्थव्यवस्था की तीव्रता 45 प्रतिशत से ज्यादा कम करने तथा वर्ष 2070 तक 'निवल शून्य' उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक केंद्रीय बैंक के रूप में, हमारे पास निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी है जिसमें कम-कार्बन अर्थव्यवस्था में अंतरण शामिल है।

बैंक टिकाऊ और हरित परियोजनाओं के साथ-साथ हरित पहल को प्रोत्साहित करने वाले नए वित्तीय उत्पादों को विकसित करके कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में अंतरण के लिए वित्तपोषण में एक आवश्यक भूमिका निभा सकते हैं। हमारे कार्य न केवल ग्रह के भविष्य के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करेंगे, बल्कि यह भी निर्धारित करेंगे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का वातावरण देते हैं।

एक विकसनशील देश में एक नियामक के लिए, प्रौद्योगिकी को अत्यंत तेजी से अपनाना, बाजार नवाचारों के साथ तालमेल रखना हमेशा एक चुनौती होती है। इस तरह के एक गतिशील वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने का वर्णन बहुत उपयुक्त रूप से "बस जब हमने सोचा कि हम सभी उत्तर जानते हैं, तो किसी ने सवालों को बदल दिया" के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि ग्राहकों को वित्तीय नवाचार के परिणाम का आनंद लेने के लिए, इसे टिकाऊ और एक मजबूत नियामक ढांचे के दायरे में होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने उत्तरदायी नवाचार के उद्देश्य से एक सूक्ष्म और परामर्शी दृष्टिकोण का पालन किया है, जबकि उद्योग को टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

समापन विचार

हमारे लिए इस तथ्य से अवगत होना महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत और लचीली वित्तीय प्रणाली का आधार लोगों का उस पर भरोसा है। विश्वास तत्व न केवल व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा बल्कि वित्तीय प्रणाली में कार्यरत संस्थाओं के सामूहिक कार्यों द्वारा भी बनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि कंपनियां अपने कार्यों और अपने द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी और इसके लिए जवाबदेही प्रदर्शित करेंगी। वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए लागू नियमों का अनुपालन और ग्राहक-केंद्रितता सुनिश्चित करना दो गैर-परक्राम्य सिद्धांत हैं और उन्हें शीर्ष से प्रवाहित किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बैंकिंग क्षेत्र भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और यह महत्वपूर्ण है कि बैंक अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलते समय के अनुसार नवाचार और अनुकूलन जारी रखें। जैसा कि भारत आगे बढ़ रहा है, बैंकिंग क्षेत्र, अब तक, देश की विकास कहानी में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना रहना चाहिए। हमेशा की तरह, आरबीआई में हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र और अन्य हितधारक भारत के लिए एक मजबूत, अधिक समावेशी और स्थायी भविष्य बनाने में मदद कर सकें।

धन्यवाद।